

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 17/23

GCMS NO 2023/14

1. रमेश
2. कांजी
3. गोरीलाल
4. घनश्याम पिसरान रामनारायण जातियान बैरवा निवासीयान संजय कालोनी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
5. धरणी पुत्री रामनारायण पत्नि हीरालाल जाति बैरवा निवासी टोडाभीम तहसील व जिला करौली
6. कैलाश पुत्र भरोसी जाति बैरवा निवासी मकनपुर तहसील सपोटरा जिला करौली
7. शारदा पुत्री भरोसी पत्नि रामेश्वर निवासी रानोली तहसील नादौती जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. किशोरी
2. बाबूलाल
3. रामजीलाल पिसरान पिल्लू जाति बैरवा निवासी ग्राम माच तहसील व जिला करौली हाल चूली की बगीची गंगापुर सिटी
4. भूमि विकास बैंक शाखा गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर जरिये शाखा प्रबंधक
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

(अपील विरुद्ध मु0नं0 82/22 निर्णय व डिक्री दिनांक 01.12.2022 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी )


अभिभाषक अपीला0 श्री के0एल0योगी  
अभिभाषक रैस्पो0 श्री विनोद अग्रवाल

दिनांक 16.12.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 01.12.2022 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलांट ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 207 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत इस आशय का किया कि वादीगण के बाबा पन्ना पुत्र जयराम की खातेदारी भूमि सम्वत 2003 ख0न0 700 रकबा की

  
राजस्व अपील प्राधिकारी

17 विस्वा ख0न0 708 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा ग्राम चूली मे स्थित है। जिसके एकीकरण मे ख0न0 479 कायम हुए। पन्ना के मरने के बाद खातेदारी उनके पुत्र रामनारायण पुत्र पन्ना के नाम विरासत से दर्ज हो गई तथा सेटलमेंट ने उक्त भूमि के नये ख0न0 742 रकबा 1.07 है0 कायम किये गये। हाल ख0न0 742 रकबा 1.07 है0 ग्राम चूली वादीगण की पैतृक आराजीयात है। जिससे ही वादीगण उक्त भूमि के मृतक रामनारायण के साथ कोशेयरर है। रामनारायण के मरने के बाद ही उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा रहा है तथा वादीगण भूमि से लाभान्वित होते चले आ रहे हैं। वादीगण के पिता रामनारायण नशे के आदि रहे हैं वादीगण के परिवार मे घरू खर्च रूपये की ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं थी वादीगण स्वयं के बालिंग होने के बाद से ही खेती एवं मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे हैं तथा वादीगण संख्या 1 ता 2 सरकारी कर्मचारी रहे हैं। उन्हे रूपये की भी कोई आवश्यकता नहीं रही। रामनारायण पुत्र पन्ना सरकारी सेवा मे रहे हैं। दिनांक 15.3.22 को वादीगण अपने खेतो पर कार्य कर रहे थे इतने मे प्रतिवादीगण मौके पर आ गये तथा वादीगण को धमकी दी यह भूमि हमने रामनारायण से क्रय कर ली है अब हम इस भूमि पर कब्जा करेगे। इस बात पर हमने प्रतिवादीगण से कहाँ कि तुमने विक्रय पत्र को छुपाकर क्यों रखा है। विवादित भूमि रामनारायण की पैतृक आराजीयात है इसलिए उसको बेचने का अधिकार रामनारायण को नहीं है। रामनारायण के साथ साथ वादीगण 1/5, 1/5 हिस्से के कोशेयरर है। तथाकथित विक्रय पत्र को यदि सही भी माना जावे तो रामनारायण को उक्त भूमि मे से 1/5 हिस्से से ज्यादा बेचने का अधिकार नहीं है। क्योंकि उक्त भूमि मे 4/5 हिस्से के वादीगण कोशेयरर है। वादीगण उक्त विक्रयपत्र को अपने हिस्से 4/5 की हद तक प्रभावशून्य घोषित कराने के अधिकारी है। वादी को उक्त विक्रयपत्र की आड मे प्रतिवादीगण अपने हिस्से से बेदखल करने पर आमादा है। इस कारण प्रतिवादीगण को भूमि ख0न0 742 रकबा 1.07 है0 से बेदखल नहीं करने तथा वादीगण के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न नहीं करने तथा भूमि को दीगर व्यक्तियों को रहन बेचान नहीं करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण द्वारा चाही गई।


प्रतिवादीगण की ओर से अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 31.10.22 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 व धारा 151 सीपीसी का पेश किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण का दावा संख्या 82/2022 एवं प्रार्थना पत्र स्थाई निषेधाज्ञा संख्या 67/22 खारिज किये जाने से व्यथित होकर वादीगण/अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्प0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

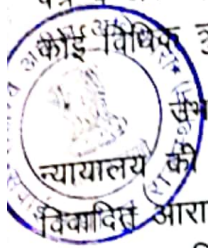
  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश में अंकित किया है कि पंजीकृत विक्रय पत्र को प्रभावशून्य घोषित कराने के विधि विरुद्ध अधियाचना की गई है। विक्रय पत्र के संदर्भ में सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। जो एकदम गलत है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा पैतृक भूमि में अपने हिस्से की भूमि की घोषणा करवाने के लिए वाद पत्र पेश किया गया था। विवादित आराजीयात कृषि भूमि है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। अपीलार्थी/वादीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त कराने का अनुतोष नहीं मांगा गया है। बल्कि अपीलार्थी के हिस्से तक प्रभावशून्य घोषित कराने की मांग की है। जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धान्त पारित किया बाबजूद अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर कानूनी भूल की है। प्रत्यर्थागण के उक्त क्षेत्राधिकार के आधार को जबाब दावे में लिया जा चुका था जिस पर तनकीयात कायम होने के उपरान्त ही विधिक प्रक्रिया के अनुसार साक्ष्य सबूत ग्रहण करने के उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण का निस्तारण करना था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। माननीय राजस्व मंडल व उच्च न्यायालय द्वारा मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि घोषणा के वाद को प्रारंभिक स्टेज पर आदेश 7 नियत 11 के माध्यम से निरस्त नहीं किया जा सकता है। जिसके संबंध में राजस्व मंडल द्वारा आर आर टी 2019 पार्ट 1 पेज 116 पर अपना भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाया जाकर प्रकरण में साक्ष्य सबूत ग्रहण कर निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अपीलांट/वादीगण द्वारा रेस्पो/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के हक में किये गये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.6.98 को प्रभावशून्य घोषित कराने की रिलीफ अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र में चाही गई थी। पंजीकृत विक्रय पत्र को प्रभावशून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। इस हेतु सिविल न्यायालय से रिलीफ प्राप्त किये जाने का कानून में प्रावधान है। विधि अनुसार कर्ता खानदान द्वारा सम्पत्ति का अन्तरण किये जाने के संबंध में अन्य सदस्यों को चुनौती दिये जाने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। कर्ता खानदान परिवार के हितार्थ सम्पत्ति का रहन बेचान व अन्तरण करने हेतु विधि अनुसार सक्षम है। अपीलांट के पिता रामनारायण द्वारा परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं कर्ता खानदान होने की हैसियत से अपनी खातेदारी व कब्जे काशत की आराजीयात को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से रेस्पो0 से प्रतिफल प्राप्त कर कब्जा संभलवाया गया है। अपीलांट/वादीगण द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त कराने की रिलीफ घोषणा के माध्यम से चाही गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन एवं अध्ययन किये जाने के पश्चात ही रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र आदेश 7

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर


नियम 11 जा0दी0 व धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर वादीगण/अपीलांट का वाद पत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विधि अनुरूप खारिज किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिगत त्रुटि नहीं है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।



सभ्यपक्ष अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात ख0न0 742 रकबा 1.07 है0 वाके ग्राम चूली तहसील गंगापुर सिटी मे स्थित है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 मे आरजीयात ख0न0 742 रकबा 1.07 है0 किशोरी,बाबूलाल,रामजीलाल पुत्रान पिल्लू जाति बैरवा निवासी ग्राम मांच तहसील करौली राहिन स.मा.सह.भूमि विकास बैंक शाखा गंगापुर सिटी के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी सम्वत 2015 से 2017 मे उक्त आराजीयात रामनारायण पुत्र पन्ना जाति बैरवा के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2070 से 2071 मे आराजीयात किशोरी,बाबूलाल,रामजीलाल पुत्रान पिल्लू जाति बैरवा के नाम का अंकन होते हुए गैहू की फसल काश्त होने का अंकन है। अपीलांट का कथन रहा कि विवादित आराजीयात पैतृक है। इस बाबत अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। अपीलांट के पूर्वज रामनारायण पुत्र पन्ना द्वारा आराजीयात को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से रेस्प0/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को विक्रय किया गया है। जो उप पंजीयक गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 15.6.98 को पंजीवद्ध किया गया है। चूकि भूमि अपीलांट के पूर्वज रामनारायण द्वारा रेस्प0/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को बेचान किया गया है जिसको निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं होने से ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/रेस्प0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 व धारा 151 सीपीसी को विधि अनुसार स्वीकार किया जाकर वादी/अपीलांट का वाद पत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया है। जो विधि के अनुरूप होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी के मु0नं0 82/22 निर्णय व डिक्री दिनांक 01.12.2022 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
(लक्ष्मीकांत बालोत)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधीपुर